

'kgjhdj .k dk i ; kbj .k ij çHkko&, d Hk&ksfyd vè; ; u

M,- Jherh fdj .k dèkj

I g çkè; ki d

'kkl - , e dch dyk , oaf .kT; efgyk egkfo |ky;] tcyij ½-i½

Abstract ½ kj½

आधुनिक युग में शहरीकरण आर्थिक विकास का एक अनिवार्य चरण बन चुका है। विश्व स्तर पर तीव्र गति से बढ़ती शहरी जनसंख्या ने पर्यावरणीय संसाधनों पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न किया है। प्रस्तुत शोध पत्र में शहरीकरण से उत्पन्न सामाजिक आर्थिक एवं पर्यावरणीय प्रभाव, जैसे वायु एवं जल प्रदूषण का बढ़ना, ठोस अपशिष्ट का निबटान समस्या, हरित क्षेत्र में कमी, जैसी समस्याओं पर भौगोलिक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यह अध्ययन द्वितीय आंकड़ों पर आधारित है तथा सतत विकास की अवधारणा के अंतर्गत समाधान प्रस्तुत करता है।

ef; 'kln & वैश्विकरण, विकासशील, सतत विकास, पलायन, जनसहभागिता शहरीकरण, पर्यावरण आदि।

çLrkouk %

शहरीकरण एक बहुआयामी सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक प्रक्रिया है। जिसके अंतर्गत जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र से बेहतर जीवन जैसे बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, उत्तम शिक्षा व्यवस्था एवं रोजगार के अवसरों की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरित होती है। परन्तु यह पलायन विभिन्न प्रकार की समस्याओं को भी जन्म देता है। तकनीकी प्रगति, वैश्विकरण, औद्योगिकरण तथा सेवा क्षेत्र के विस्तार ने शहरीकरण को तीव्र गति प्रदान की है। जिससे शहरों में पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2050 तक विश्व की कुल जनसंख्या में से लगभग 68% जनसंख्या शहरी क्षेत्र में निवास करेगी। जबकि विकासशील देशों में यह प्रक्रिया और भी तीव्र होगी जो शहरीकरण के विकास के साथ-साथ पर्यावरणीय संकट को भी जन्म देगी।

vè; ; u dk míf; %

- (i) शहरीकरण के कारणों का भौगोलिक विश्लेषण करना।
- (ii) पर्यावरण पर शहरीकरण के प्रभाव का विश्लेषण प्रस्तुत करना।
- (iii) शहरीकरण और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन हेतु उपाय सुझाना।



वृद्धि और

यह शोध पत्र द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित है इसमें उपलब्ध आंकड़ों व उदाहरण के आधार पर शहरीकरण का पर्यावरण पर प्रभाव का विश्लेषण किया गया है । अध्ययन के आधार पर समाधान एवं निवारण की संभावनाओं को रेखांकित किया गया है। विभिन्न पुस्तकों शोध पत्रों सरकारी रिपोर्ट तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट का अध्ययन भी शामिल है।

'कृषि के विकास

भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया का इतिहास प्राचीन काल से जुड़ा हुआ है प्राचीन भारत में पाटलिपुत्र, उज्जैन, प्रयाग, वाराणसी, नालंदा, तक्षशिला जैसे नगरों का विकास राज्यों की राजधानी या व्यापारिक, धार्मिक एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित हुए। इसी प्रकार मध्य काल में आगरा, दिल्ली, अहमदनगर, बुरहानपुर, जैसे नगर स्थापित एवं विकसित हुए। ब्रिटिश शासन काल में भारत के कई नगर प्रशासनिक एवं व्यापारिक केन्द्रों के रूप में विकसित हुए जैसे कोलकाता, मद्रास, मुंबई और नई-दिल्ली जैसे नगर औद्योगिक तथा वाणिज्यिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र बने। परंतु आधुनिक शहरीकरण औद्योगिक विकास एवं व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार के साथ और तीव्र हुआ है। इन नगरों में उद्योगों की स्थापना के कारण रोजगार के अवसर बढ़े और ग्रामीण क्षेत्रों से लोगों का पलायन शहरों की ओर होने लगा स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शहरीकरण की प्रक्रिया और तेज हुई इस समय भिलाई धनबाद, टाटानगर, राउरकेला, भोपाल, इन्दौर जैसे नगर अस्तित्व में आये। विशेष कर 20वीं सदी के आखरी दो दशकों में भारत सरकार ने शहरी विकास को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं बनाई और शहरी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार किया। वैश्वीकरण और खुली बाजार नीतियों के परिणामस्वरूप भारत के कई छोटे शहरों में व्यापार, उद्योग, एवं शिक्षा के केंद्र के रूप में, विकसित होकर महानगर का रूप लिया है। जैसे हैदराबाद, पुणे, बेंगलुरु, नोएडा, गुरुग्राम, अहमदाबाद इत्यादि। इन नए शहरों में पिछले 25 से 30 वर्षों में देश के विभिन्न हिस्सों से पलायन के कारण जनसंख्या में अप्रत्याशित वृद्धि दर्ज की गयी है।

'कृषि के विकास

निःसंदेह रोजगार के अवसर, शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, परिवहन, तथा प्रशासनिक सुविधाएँ, ग्रामीण जनसंख्या को नगरों की ओर आकर्षित करती हैं और ये सुविधाएं ग्रामों एवं छोटे कस्बों से अधिक होती हैं। परन्तु वर्तमान में शहरीकरण एक गंभीर समस्या के रूप में उभर कर सामने आयी है। भारत की शहरी आबादी वर्ष 2030 तक लगभग 60 करोड़ से ऊपर पहुंचने की संभावना है, साथ ही वर्ष 2035 तक यह लगभग 67.5 करोड़ तक हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्र से लोग लगातार पलायन के कारण शहरों का बेतर्ती विकास हुआ है । जिससे मास्टर प्लान भी सफल नहीं हो पा रहे हैं । सड़कों, सीवर सिस्टम, पार्किंग और कचरा प्रबंधन जैसे बुनियादी ढांचों पर अत्यधिक दबाव है। सड़कों का सफा होना वाहनों की संख्या में बेतहासा वृद्धि और सड़कों के खराब डिजाइन के कारण, लंबा ट्रैफिक जाम शहरों में आम हो चला है नोएडा एवं बेंगलुरु जैसे शहरों के ट्रैफिक जाम और पानी की कमी राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों के प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित होते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक सन 2050 तक दो तिहाई आबादी नगरों में रहने लगेगी और एक तिहाई आबादी तटीय इलाकों में रहने को विवश हो जाएगी। इतनी जगह भी नहीं बचेगी की लोग सुरक्षित भूमि पर अपना घर बना सके विश्व स्वास्थ्य संगठन रिपोर्ट 2022 के अनुसार विश्व की 99 प्रतिशत जनसंख्या प्रदूषित वायु में सांस लेने को मजबूर है। दिल्ली का वायु प्रदूषण प्रति वर्ष सर्दियों में



राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अखबारों के साथ टेलिविज़न डिबेट का मुख्या मुद्दा रहता है, तथा सरकारों के लिए चुनौती बन गया है। इसी प्रकार ठोस अपशिष्ट निस्तारण भी विकराल समस्या बनकर उभरा है। दिल्ली का कूड़े का पहाड़ तो चुनाव का मुद्दा बन गया था जो अब भी नई सरकार के लिए चुनौती है। यही हाल अन्य शहरों का भी है साथ ही जल प्रदूषण ना केवल पर्यावरण के लिए समस्या है अपितु पीने के पानी की गंभीर समस्या बनी है। हाल ही में इन्दौर शहर में दूषित पानी से हुई मौते राष्ट्रिय मुद्दाबना है। वायु प्रदूषण पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने के साथ जीव जंतुओं, अन्य वनस्पतियों और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है। मानसिक तनाव अनिद्रा चिड़चिड़ापन, उच्च रक्तचाप जैसी समस्याएँ अब आम हो चली है। शहरों में अवैध कालोनियों एवं गंदी बस्तियों के निर्माण से स्वास्थ्य एवं जीवन स्तर में गिरावट आम हो चला है। बेरोजगारी, शहरी गरीबी में वृद्धि, बुनियादी सुविधाओं पर दबाव, जल संकट और जल भराव, यातायात, पानी, बिजली, आवास की कमी के साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव और पर्यावरण समस्याएं जैसे वायु प्रदूषण, तापमान में बढ़ोतरी, तूफान, जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों को यदि समय रहते नियंत्रित नहीं किया गया तो यह और विकराल होती जाएंगी। हालाँकि सरकारें मास्टर प्लान और ग्रामीण शहरी विकास योजनाओं के माध्यम से इसे हल करने का प्रयास कर रही है। परन्तु बढ़ती जनसंख्या भी इस का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। बेहतर प्रबंधन का ना होना आने वाली पीढ़ी के लिए गंभीर समस्या बन जाएगी। साथ ही नागरिकों में सिविक सेंस जागृत करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि कई समस्याएं इंसानों द्वारा या शहरी निवासियों द्वारा सिविक सेंस के ना होने के कारण विकराल रूप धारण कर रही है। उदाहरण के लिए पॉलिथीन का प्रयोग न केवल ठोस अपशिष्ट को बढ़ाता है बल्कि नालियों में जाकर उन्हें चोक कर वर्षा के दौरान जल भराव को बढ़ाता है साथी अन्य जानवरों के लिए भी हानिकारक साबित होता है ट्रेफिक नियमों का सही से पालन न करना भी लंबे ट्रेफिक जाम का कारण बनता है ।

1.4.10 Suggestions

- शहरी विकास को सतत विकास (Sustainable Development) की अवधारणा से जोड़ा जाए।
- शहरी क्षेत्रों में हरित पट्टियों, पार्को एवं शहरी वनों का विकास किया जाए।
- सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को सुदृढ़ किया जाए तथा निजी वाहनों की संख्या नियंत्रित की जाए।
- ठोस अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली को वैज्ञानिक तरीके से लागू किया जाए तथा प्लास्टिक के उपयोग को सीमित किया जाए।
- वर्षा जल संचयन एवं भूजल पुनर्भरण को अनिवार्य बनाया जाए।
- औद्योगिक उत्सर्जन पर कठोर नियंत्रण एवं स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा दिया जाए।
- नागरिकों में पर्यावरण जागरूकता एवं सिविक सेंस विकसित करने हेतु अभियान चलाए जाएँ।
- शहरी नियोजन में मास्टर प्लान का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में भी बुनियादी सुविधाओं का विकास सुनिश्चित किया जाए विशेषकर सड़क परिवहन एवं स्वास्थ्य ।
- ग्रामीण, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के साथ-साथ MSME क्षेत्र को प्रोत्साहन एवं विकास में सहयोग पलायन को कम कर सकता है।



Conclusion

शहरीकरण आर्थिक विकास का महत्वपूर्ण साधन है, किंतु अनियोजित एवं अनियंत्रित शहरी विस्तार पर्यावरणीय असंतुलन को जन्म दे रहा है। वायु प्रदूषण, जल संकट, ठोस अपशिष्ट, हरित क्षेत्र में कमी तथा शहरी ऊष्मा द्वीप प्रभाव जैसी समस्याएँ तेजी से बढ़ रही हैं।

यदि समय रहते वैज्ञानिक शहरी नियोजन, पर्यावरणीय नीतियों का प्रभावी क्रियान्वयन तथा जनसहभागिता सुनिश्चित नहीं की गई, तो भविष्य में स्थिति और गंभीर हो सकती है। अतः आवश्यक है कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के मध्य संतुलन स्थापित किया जाए, जिससे वर्तमान एवं भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण सुनिश्चित किया जा सके।

References

- संयुक्त राष्ट्र (United Nations). World Urbanization Report-
- विश्व बैंक (World Bank). Urban Development Indicators Report-
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO). Air Quality Report 2022.
- भारत सरकार, आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की रिपोर्टें।
- जनगणना भारत (Census of India) रिपोर्ट 2011 एवं प्रावधिक अनुमान।
- सिंह, आर. एल. (Urban Geography).

